Mercredi 21 novembre 2012

HIN3A13a

(Expression orale)

Cours-8

Comment mesure-t-on le seuil de pauvreté et quel est l'enjeu de cette statistique ?

गरीबी का आकलन

संपादकीय / May 06, 2012 बिज़नेस स्टैंडर्ड

गरीबी के अनुमानों ने एक बार फिर इस गैर जरूरी बहस-f débat को जन्म दे दिया है कि इसके आकलन-m évaluation का तरीका क्या हो। वर्ष 1973 के बाद कई वर्षों तक सरकार ने एक साधारण तरीके का इस्तेमाल किया : अगर कोई परिवार अपने सदस्यों के लिए कैलोरी की खास मात्रा और कपड़े आदि नहीं खरीद पाता है तो उसे योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे माना जाता। लेकिन इसमें एक समस्या थी - सर्वेक्षण में शामिल किए जाने वाले लोगों में अपना खर्च कम बताने की प्रवृत्ति-f tendance देखी जा रही थी और इसलिए अतीत-m passé में बताए गए खर्च को वास्तविक खर्च से कम माना जाता और इस तरह कम बताये गए खर्च का समायोजन-m ajustement कर लिया जाता। बहरहाल cependant, जब गरीबी में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई तो सरकार ने आकलन के तरीके में बदलाव आरंभ किया। इनमें से हर परिवर्तन का लक्ष्य-m objectif केवल एक ही है - यह सुनिश्चित करना कि गरीबी का स्तर-m niveau बढ़ा हुआ दिखे। पहले बताए गए खर्च को वास्तविक खर्च माना गया जिससे सीधे तौर पर गरीबों के आंकड़ों-m statistiques में इजाफा-m augmentation देखने को मिला। इसके बाद सरकार ने अन्य खर्चों मसलन, शहरी शिक्षा खर्च आदि को गरीबी रेखा के आकलन से जोड़ दिया। इससे एक बार फिर गरीबों की अनुमानित संख्या में बढ़ोतरी-f augmentation देखने को मिली। इसके पश्चात après सरकार ने एक नए सर्वेक्षण-m sondage की आवश्यकता महसूस की-हालांकि वह उन मानकों-m standard को लेकर सुनिश्चित नहीं थी कि नई गरीबी रेखा निर्धारित करने के मानक दरअसल क्या होंगे? गरीबी पर इस अनावश्यक हंगामे-m boucan का प्रमुख हिस्सा दो बातों पर टिका है। पहला है बताए गए खर्च और वास्तविक खर्च में अंतर। विभिन्न राष्ट्रीय नमूना-m spécimen सर्वेक्षणों में बताए गए खर्च का जोड़ राष्ट्रीय लेखा-m comptabilité सांख्यिकी-f statistiques द्वारा बताए गए वास्तविक खर्च के आधे से भी कम है। दूसरी बात है हमारी यह नई मान्यता-f reconnaissance कि समावेशन के लिए केवल कैलोरी नहीं बल्कि बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और ऐसी तमाम जरूरतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस तरह यह स्पष्ट है कि गरीबी रेखा के लिए एक और सर्वेक्षण को अंजाम देने से बात नहीं बनेगी। लोग गलत जानकारियां देंगे इस उम्मीद में कि अगर वे कम खर्च बताएंगे तो शायद उनको कल्याण-m protection social योजनाओं का लाभ मिलेगा। न ही इस पर कोई सहमति बन पाएगी। अधिक बुरी बात यह है कि अगर नई गरीबी रेखा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर आधारित नहीं हुई तो इसकी पिछली रेखाओं से तुलना तक नहीं की जा सकेगी। समय-समय पर इसकी तुलना की जानी आवश्यक है। अगर गरीबी में कमी आने के संकेत मिलेंगे तो नीति निर्माता विकास को गति दे सकेंगे या वह तय कर सकेंगे कि कल्याण योजनाओं में खर्च करना है या नहीं। इसके अलावा en outre, अगर हम कैलोरी आधारित गरीबी से निजात-f débarras पाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी न्यूनतम minimum आधारभूत fondamental जरूरतों पर ध्यान देना होगा। समस्या का हल-m solution यह मान लेने में छिपा है कि गरीबी के अनेक स्तर हैं। उच्चतम स्तर पर कैलोरी आधारित गरीबी है, जिसे अधिकतम गरीबी रेखा कहा जा सकता है। अगला कदम-m pas, mesure है शिक्षा जैसी मूल जरूरतों पर आधारित गरीबी जिसे मूल जरूरत पर आधारित गरीबी रेखा कहा जा सकता है। अंतिम रेखा विकसित देशों पर आधारित मानकों पर हो सकती है जिसे अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा करार दिया prescrire जा सकता है। इन मानकों के आधार पर नमूना सर्वेक्षण के इस्तेमाल के साथ गरीबी में आने वाले बदलावों का आकलन किया जा सकता है। अगर इनमें से किसी एक मानक के आधार पर गरीबी का स्तर कम हो जाता है तो नीतियों को ऊंचे स्तर की गरीबी से निपटने के लिए बदला जा सकता है। यह गरीबी से निपटने का ज्यादा पारदर्शी transparent और ईमानदार तरीका है।